



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 11

दर्ज तिथि:-08.01.2024

1. पूनमाराम पुत्र वालाराम
2. ओखाराम पुत्र वालाराम
3. जेठाराम पुत्र रामजीराम
4. जीवाराम पुत्र वालाराम
5. जोगाराम पुत्र चिमनाराम
6. जोराराम पुत्र जगरूपाराम
7. डूंगराराम पुत्र वालाराम
8. तुलछाराम पुत्र वालाराम
9. निम्बाराम पुत्र वालाराम
10. प्रभा पत्नी वालाराम
11. मांगाराम पुत्र करनीया
12. राणाराम पुत्र चिमनाराम
13. सुरताराम पुत्र रामजीराम
14. सरूपाराम पुत्र चिमनाराम
15. हिमताराम पुत्र वालाराम

जाति राईका निवासी बारासण तहसील गुडामालानी-बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

1. छटी पत्नी फुसाराम
2. तुलछा पुत्र फुसाराम
जाति मेघवाल निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी-बाड़मेर
3. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी।
4. तहसीलदार गुडामालानी
5. कृष्ण पुत्र बींजाराम
6. कोंकूदेवी पत्नी मलाराम
7. पपूराम पुत्र मलाराम
8. प्रभुराम पुत्र बींजाराम
9. बादली पत्नी बींजाराम
10. रदा पुत्र दजाराम
11. श्रवण कुमार पुत्र मलाराम
12. सदराम पुत्र मांगाराम
जाति भांभी निवासी जीवाणियों की ढाणी बारासण
13. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी गुडामालानी

.....अप्रार्थीगण



उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री गंगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-10.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 486/2.0477 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 768/4.5325 है0 मौजा बारासण से होते प्रार्थीगण के खेत तक विद्यमान रास्ता मौके पर चालू है। उक्त विद्यमान रास्ते में खसरा संख्या 768 में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है तथा विप्रार्थीगण वक्त काश्त उक्त खसरों में काश्त कर लेते हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपने जोत तक आने-जाने से बाधित हो जाते हैं। अतः खसरा संख्या 768 के सेढे से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल के पश्चात् हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 767 से होकर ही प्रार्थीगण आवागमन करते आए हैं। खसरा संख्या 768 में पहले ही बहुत सारी आराजी नहर में अवाप्त किये जाने से अप्रार्थीगण के पास बहुत कम आराजी बची है। साथ ही खसरा संख्या 767 से होकर रास्ता ही नवीनतम दूरी का रास्ता है। अतः खसरा संख्या 767 में से होकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी हाजा न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/183 दिनांक 11.03.2024 से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जाँच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।
3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना-पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where -

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional

Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) *The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. प्रार्थी की रास्ते बाबत् अन्य रिकार्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तों के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया

है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 486 मौजा बारासण तक पहुंचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 768 मौजा बारासण में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता की अनुपस्थिति रिकॉर्ड एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौड़ाई का लघुत्तम मार्ग रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 486 मौजा बारासण में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 768 मौजा बारासण में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 768 मौजा बारासण के सेढे से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 768 मौजा बारासण से होकर प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 767 मौजा बारासण से होकर वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मार्ग ही लघुत्तम व व्यावहारिक मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रस्तावित वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
5. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक

रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काबिल-ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 767 में से गहरे लाल रंग से अंकित मार्ग पर गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1188 दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं विश्लेषित निष्कर्षानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 767 मौजा बारासण से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 486 तक प्रार्थी द्वारा वांछित/इच्छित चौड़ाई, जो कि चौड़ाई में अधिकतम 30 फीट तक हो, के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम-70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के नियमानुसार भुगतान पश्चात् अथवा अथवा प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या-1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी-बाड़मेर